small consumers are always kept at bay. Thus, the small consumers do not have any other way except to buy coal from the highest bidders at exorbitant prices. The result is, prime coal is now being sold in the market at Rs. 4,000-5,000 per tonne. This system is resulting in black-marketing. Hence, it is requested that some portion of coal be kept aside for SSIs, small factory owners so that they are not affected by the highest bidders and consumers get end product at cheaper price.

Demand to approve the proposal of Himachal Pradesh Government to levy generation Tax on Hydel power production

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, हिमाचल प्रदेश की बहती नदियों में 20376 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर जेनरेशन टैक्स लगाने का मामला पिछले तीन दशकों से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन बार-बार केन्द्र सरकार इसे टालती जा रही है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण राजस्व प्राप्ति के लिए मुख्यत: प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जिनमें वन एवं जल विद्युत दोहन प्रमुख हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वर्ष 1982 में सी. रंगराजन समिति ने इस प्रकार का टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। 1984-85 में सरकार ने विद्युत उत्पादन पर ड्यूटी को भी वापस ले लिया था ताकि राज्य सरकारें इस विषय पर स्वयं निर्णय ले सकें। 27 सितम्बर, 1995 को प्रदेश विधान सभा द्वारा बिल पारित किया गया था, जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित पड़ा है। 13 अगस्त, 2009 को हिमाचल विधान सभा ने प्रस्ताव पारित कर महामहिम राष्ट्रपति से इस आशय के बिल पर सहमति हेतु अनुरोध किया है। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय वित्त एवं विधि मंत्रालय ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की है, जबकि ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि संविधान की धारा 288 के अनुसार राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती, जबकि इसी धारा की उप-धारा (2) में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की सहमति से राज्य सरकार इस प्रकार का टैक्स लगा सकती है। अत: मेरा अनुरोध है कि राज्य के बढ़ते राजस्व घाटे पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार अति शीघ्र इस मामले पर निर्णय कर हिमाचल प्रदेश को समुचित न्याय दिलवाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up further discussion on Budget (General) 2011-12. Shrimati Brinda Karat. ...*(Interruptions)*...

श्री राशि अल्वी (आंध्र प्रदेश): सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री उपसभापति: हो गया.... हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशिद अल्वी: सर, कर्णाटक के जो मुख्यमंत्री ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं ...(**व्यवधान**)... आपको यह जीरो ऑवर में उठाना चाहिए था। ऐसा करना ठीक नहीं है। श्रीमती वृंदा कारत, बोलिए। ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: *

श्रीमती विप्लव ठाकुर: *

श्री उपसभापति: आप खामोश रहिए। आप क्यों बात कर रही हैं। श्रीमती वृंदा कारत। ...(**व्यवधान**)...

श्री राशि अल्वी: *

श्री उपसभापति: आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। Please. ...*(Interruptions)*... You have to give proper notice. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. अल्वी साहब, आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री राशिद अल्वी: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... पाणि जी, आप बैठ जाइए। पाणि जी, आप बैठ जाइए। श्रीमती वृंदा कारत। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए। पाणि जी, आप बैठ जाइए। आप खामोश बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

THE BUDGET (GENERAL), 2011-12

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I thank you for giving me this opportunity to express my party's view on the Budget.

Sir, I stand here in opposition ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate has started. Be serious.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, please cut that minute. I should get one more minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I stand in opposition to the general direction and the intent of this Budget which is to further the neoliberal agenda which is being set out in the Economic Survey. And it is regretful, Sir, that this Government seems to have learnt no lessons at all from the global

*Not recorded.